

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.nic.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 60 ● अंक 17 ● भोपाल ● 1-15 फरवरी, 2017 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

गण और तंत्र के रिश्तों को मजबूत बनाया सरकार ने

गणतंत्र दिवस पर नागरिकों के नाम मुख्यमंत्री श्री चौहान का सन्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों से विकसित समाज गढ़ने और नई पीढ़ी को भयमुक्त, निष्पक्ष और कानूनप्रिय वातावरण देने के लिए शत-प्रतिशत योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर रहते हुए विकसित राज्यों की श्रेणी में आने की कगार पर है। गणतंत्र दिवस पर अपने सन्देश में उन्होंने नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएँ दी।



मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गण और तंत्र के रिश्तों को मजबूत बनाने में सफल रही है। संवैधानिक संस्थाएँ मजबूत हुई हैं। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में लगातार 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री द्वारा नोटबंदी के जरिये काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के विरुद्ध मुहिम का जिक्र करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह तभी प्रभावी होगी जब काला धन पैदा करने वाले तरीकों पर प्रहार करें। कैशलेस लेन-देन के जरिये काले धन पर नियंत्रण प्रभावी हो पाएगा।

उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि वे काले धन के विरुद्ध इस मुहिम में अपनी सक्रिय भागीदारी दें।

नर्मदा सेवा यात्रा

नमामि देवी नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी संरक्षण के विश्व के इस सबसे बड़े अभियान ने सर्वधर्म समभाव को हकीकत में बदला है। यात्रा में सभी धर्मों और वर्ग के लोग स्वेच्छा से शामिल होकर माँ नर्मदा की सेवा और पर्यावरण संरक्षण की अलख जगा रहे हैं।

जन-सहभागिता से संचालित इस यात्रा में नर्मदा नदी के दोनों तट

पर वृक्षारोपण, सीवेज और पूजन सामग्री नदी में नहीं डालने और पार्थिव शरीर जल-समाधि नहीं देने, नशा नहीं करने तथा बेटी बचाने के लिये संकल्प लिया जा रहा है। वृक्षारोपण शासकीय भूमि पर सरकार और निजी भूमि पर किसान करेंगे। किसानों को इसके लिये 3 वर्ष तक 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष प्रोत्साहित करने के लिये दिया जायेगा। नर्मदा तटों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने, मुक्तिधाम और विसर्जन कुण्ड बनाने, घाटों के सुधार और महिलाओं के लिये चेंजिंग रूम बनवाने की कार्य-योजना बनायी

गई है।

शराब दुकानें बन्द

मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 जिलों में नर्मदा तट के 5 किलोमीटर की परिधि में 58देशी-विदेशी शराब दुकानों को बन्द करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे पूरे प्रदेश में शराब पीने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने आगे आएँ।

प्रदेश में 14 से 21 जनवरी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 7500 स्थलों पर आयोजित आनंद उत्सव की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं में आनंद

सभाएँ और शासकीय कार्यालयों में अल्प विराम कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आनन्दम कार्यक्रम के संबंध में कहा कि जिन लोगों के पास उनकी जरूरत ज्यादा सामान है वे एक निश्चित स्थान पर दान देने का आनंद उठा सकते हैं।

दीनदयाल थाली

मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल माह से गरीबों के लिये दीनदयाल थाली की योजना चुनिंदा शहरों से शुरू की जायेगी।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

सहकारी बैंकों का सदस्य बनाने के लिए 'घर वापसी' अभियान

सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने की समीक्षा



भोपाल। किसानों को सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलवाने के लिये उन्हें सहकारी बैंकों और साख समितियों का सदस्य बनाया जायेगा। इसके लिये एक माह का घर वापसी अभियान चलाया जायेगा। सहकारिता राज्य मंत्री

(स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग प्रदेश में सहकारी आंदोलन को नई दिशा देने और मजबूत बनाने के लिये सितम्बर माह में हुई सहकारी मंथन की सिफारिशों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी,

आयुक्त सहकारिता श्री कवीन्द्र कियावत, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री प्रदीप नीखरा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने बताया कि सहकारी साख समितियों और बैंकों का सदस्य न होने के कारण

किसानों को सरकार की कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण और मूल ऋण में 10 प्रतिशत की सबसिडी का फायदा उसे नहीं मिलता है। इसलिये मंथन की सिफारिशों के आधार पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा

सहकारी मंथन की 132 में से 74 सिफारिश का क्रियान्वयन

है। इसी कड़ी में 26 जनवरी से 26 फरवरी तक घर वापसी अभियान में किसानों से सम्पर्क कर उन्हें वाणिज्य बैंकों के स्थान पर सहकारी बैंकों से जोड़ा जायेगा।

श्री सारंग ने बताया कि सहकारी मंथन में 132 सिफारिश में से 74 पर क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। शेष पर कानूनी और एक्ट में परिवर्तन संबंधी कार्यवाही चल रही है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल में किया ध्वजारोहण

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 68वें गणतंत्र दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने परेड का निरीक्षण भी किया। हर्ष फायर के बीच पुलिस बैण्ड दल ने राष्ट्र गान जन-गण-मन की धुन बजाई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हर्ष के प्रतीक रंगीन गुब्बारे भी छोड़े। हर्ष फायर के बीच पुलिस बैण्ड दल ने सेवानिवृत्त निरीक्षक श्री शेख रजा उल्लाह के निर्देशन में "जन गण मन" की धुन बजाई। हर्ष फायर के बाद परेड कमाण्डर एस.डी.ओ.पी. बालाघाट श्री प्रदीप शर्मा (भापुसे) और परेड के टू-आई सी. एस.डी.ओ.पी. मण्डलेश्वर खरगोन श्री हेमंत चौहान के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस परेड का मार्च पास्ट प्रदर्शन हुआ।

परेड में निरीक्षक श्री आर.एस.मालवीय ने सीआई

एसएफ, सहायक उप निरीक्षक श्री शिवदेव सिंह ने एस.एस.बी., निरीक्षक श्री अग्नेस दुबे ने उत्तरप्रदेश सशस्त्र पुलिस, निरीक्षक श्री लखन मरावी ने मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल, निरीक्षक श्री नीरज वर्मा ने जिला बल एवं जीआरपी, निरीक्षक श्रीमती शोभना मिश्रा ने विशेष सशस्त्र बल/जिला पुलिस बल (महिला), कंपनी कमांडर श्री पी.एल. कोगे ने मध्यप्रदेश होमगार्ड, सहायक जेल अधीक्षक सुश्री हेमसरिता मिंज ने जेल विभाग, सूबेदार श्री मोहम्मद सलीम ने भूतपूर्व सैनिक, सीनियर अंडर ऑफिसर ने हा राना ने एन.सी.सी.आर्मी विंग (बॉयज), सीनियर कैडेट कैप्टन प्रवीण कुमार द्विवेदी ने एन.सी.सी. नेवल विंग, कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर विजयश्री रेवायकर ने एन.सी.सी. एयर विंग, सीनियर अंडर ऑफिसर सुरभि साहू ने सीनियर डिवीजन



एनसीसी आर्मी विंग गार्ल्स, कमाण्डर सुशील बघेल ने स्काउट्स (बॉयज), कमाण्डर आरती कुशवाह ने गाइड (गर्ल्स) और कमाण्डर नकुल मारन ने पुलिस (बॉयज) दल का नेतृत्व किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हैदराबाद में हुई डी.जी.पी. कान्फ्रेंस में अंतर्राज्यीय पुलिस समन्वय मजबूत करने के लिए गणतंत्र दिवस परेड में अन्य प्रदेश का दल शामिल करने के निर्देश दिए गए थे। इसी के अनुपालन में उत्तरप्रदेश सशस्त्र पुलिस का दल भोपाल में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ।

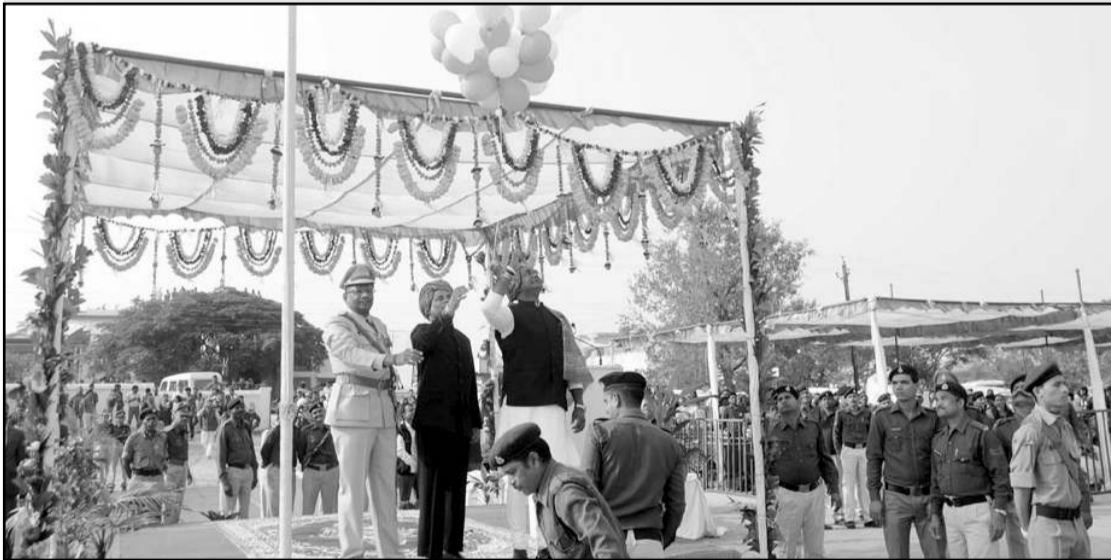
शेख रजाउल्लाह के निर्देशन में पुलिस बैण्ड ने आकर्षक संगीतमयी परेड प्रस्तुत की। उप निरीक्षक श्री अम्बिका प्रसाद दुबे के नेतृत्व में श्वान दल और उप निरीक्षक श्री चरण सिंह यादव और सुश्री धनवंतरि ठाकुर के नेतृत्व में अश्वारोही दल ने भाग लिया। परेड के बाद विभिन्न

स्कूलों के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। प्रदेश की घुड़सवारी अकादमी के घुड़सवारों ने भी अपने करतब दिखाये।

समारोह में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भोपाल संभाग कमिश्नर श्री अजातशत्रु, पुलिस महानिरीक्षक श्री योगेश चौधरी, कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े, एसएसपी श्री रमन सिंह सिकरवार, एसपी श्री अरविंद सक्सेना एवं श्री सिद्धार्थ बहुगुणा सहित वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जन-प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में कुल 18 विभाग की आकर्षक झाँकियों का प्रदर्शन किया गया।

देशभक्ति एवं सद्भावना के तरानों ने बाँधा समा

प्रभारी मंत्री श्री विश्वास सारंग ने ली परेड की सलामी



झाबुआ। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी समारोह का आयोजन शहीद चन्द्रशेखर आजाद महाविद्यालय प्रांगण झाबुआ में किया गया। कार्यक्रम में रंग-बिरंगी ड्रेस पहने विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने नृत्य, देश भक्ति गीत एवं सद्भावना गीतों के तरानों से प्रांगण में देश भक्ति का माहौल बनाया। प्रातः 9.00 बजे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री श्री विश्वास सारंग ने ध्वजारोहण किया एवं परेड की सलामी ली। तत्पश्चात प्रभारी मंत्री श्री विश्वास सारंग ने मुख्य मंत्री के संदेश का

वाचन किया। कार्यक्रम में परेड ने हर्ष फायर एवं जय घोष किया एवं मार्च पास्ट किया। मुख्य अतिथि ने परेड कमान्डरों का परिचय प्राप्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। रंग-बिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़े गये। पुलिस बेन्ड द्वारा राष्ट्रीय धुन प्रस्तुत की गई एवं विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा शासन की योजनाओं से संबंधित झाँकियों का प्रदर्शन किया गया। समारोह में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा पी.टी. एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया।

समारोह के अन्त में विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों विद्यार्थियों, समारोह में प्रदर्शन करने वाले परेड दलों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री लोकेश चौहान श्री हरिश कुण्डल एवं डॉ.गीता दुबे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी कलेक्टर एवं मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अनुराग चौधरी, विधायक झाबुआ श्री शांतिलाल बिलवाल, पुलिस अधीक्षक श्री महेश चंद जैन, सभी विभागों के शासकीय सेवक

जनप्रतिनिधिगण विद्यार्थी एवं बड़ी संख्या में नागरिक गण उपस्थित थे।

समारोह में ये हुवे पुरस्कृत

गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य हेतु विभिन्न विभागों के शासकीय सेवकों को पुरस्कृत किया गया एवं कार्यक्रम स्थल पर परेड प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार विशेष सशस्त्र बल 15 वाहिनी झाबुआ ए कम्पनी, द्वितीय जिला पुलिस बल झाबुआ एवं तृतीय होमगार्ड बल को प्रदान किया गया एवं एन.सी.सी. जूनियर में शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. झाबुआ को प्रथम एवं एन.सी.सी. सिनियर शा.महाविधलय विधालय झाबुआ को द्वितीय, पुरस्कार प्रदान किया गया। शा.क.उ.मा.विद्यालय झाबुआ रेडक्रास प्रथम एवं जूनियर रेडक्रास शा. उत्कृष्ट विद्यालय झाबुआ को द्वितीय पुरस्कार प्रदाय किया गया। बा.उ.मा.विद्यालय रातीतलाई स्काउट प्रथम, एवं निराश्रित बाल आश्रम महिला मण्डल स्काउट जूनियर द्वितीय, सात्वना में शा.क.उ. विद्यालय झाबुआ गाईड दल एवं शौर्य दल झाबुआ को सहभागिता पुरस्कार दिया गया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में जूनियर में माध्यमिक स्तर पर प्रथम पुरस्कार विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र रंगपुरा झाबुआ को, द्वितीय पुरस्कार न्यू

कन्या आश्रम शाला अंग्रेजी माध्यम झाबुआ, एवं सिनियर में प्रथम क.उ.मा. विद्यालय झाबुआ, द्वितीय शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. झाबुआ तथा तृतीय इन्दौर पब्लिक स्कूल झाबुआ, प्रोत्साहन पुरस्कार कैथोलिक मिशन स्कूल हिन्दी माध्यम झाबुआ को प्रदान किया गया। पीटी प्रदर्शन के लिये आदिवासी विकास विभाग झाबुआ को पुरस्कृत किया गया। योगा प्रदर्शन में कु. गरिमा जायसवाल को पुरस्कृत किया गया। झाँकी प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार कृषि विभाग झाबुआ, को द्वितीय पुरस्कार सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग झाबुआ, एवं तृतीय महिला एवं बाल विकास विभाग झाबुआ को प्रदान किया गया।

रंगपुरा में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ

गणतंत्र दिवस के अवसर पर विकलांग पुनर्वास केन्द्र रंगपुरा में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री श्री विश्वास सारंग, विधायक श्री शांतिलाल बिलवाल, विधायक पेटलावद सुश्री निर्मला भूरिया, प्रभारी कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री महेशचन्द्र जैन सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने विकलांग बच्चों के साथ भोजन किया।

जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न

जिले के प्रभारी मंत्री श्री सारंग द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा

अलीराजपुर । जिले के प्रभारी एवं सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने शुक्रवार को यहां कलेक्टर सभा कक्ष में जिला योजना समिति की बैठक ली । इस बैठक में खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, खनिज विभाग, शिक्षा विभाग, सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं की समीक्षा की गई ।

प्रभारी मंत्री श्री सारंग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री प्रभाकर ननावरे को पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन समय सीमा में प्रस्तुत नहीं करने पर शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर को दिए । श्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्राप्त आवंटन का समय पर उपयोग करें ।

श्री सारंग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर एक सप्ताह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए । श्री सारंग ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उदयगढ़ तथा चंद्र शेखर आजाद नगर को तत्काल हटाकर उनके स्थान पर अन्य अधिकारी को पदस्थ करने तथा इन दोनों अधिकारियों को जिला कार्यालय में पदस्थ करने के निर्देश कलेक्टर को दिए । प्रभारी मंत्री ने



कपिलधारा योजना के अंतर्गत आ रही समस्या के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर उन्हें तथा प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास विभाग को शीघ्र भेजने के निर्देश दिए । उन्होंने जिले में कडकनाथ प्रजाति के उत्पादन एवं बिक्री को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन सोसायटी बनाकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर 15 फरवरी 2017 तक प्रस्तुत करने के निर्देश उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवा को दिए । साथ ही दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अभियान चलाकर लोगों को प्रोत्साहित कर समिति के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ।

उन्होंने कहा कि जिले में रोजगार सृजन के लिए मुख्य कार्यपालन

अधिकारी जिला पंचायत के नेतृत्व में सहाकारिता, पशु चिकित्सा, कृषि और उद्यानिकी विभाग समन्वय के साथ एक वर्षीय कार्य योजना तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

उन्होंने अलीराजपुर नगर पालिका क्षेत्र में शौचालय निर्माण में की गई अनियमिता की जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जोबट से कराने के निर्देश दिए । इस जांच दल में पुलिस अधिकारी को भी शामिल करने के निर्देश दिए । यह जांच 10 फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं । उन्होंने खाद्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अनियमिताओं की जांच

खाद्य तथा राजस्व विभाग के अमले द्वारा एक माह में पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए । उन्होंने सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि 0 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराए और शत प्रतिशत किसानों को सहकारी संस्थाओं के सदस्य बनाना सुनिश्चित करें । उन्होंने जिले में स्थापित डोलामाइट फैक्ट्रियों की जांच एवं आने वाले कच्चे माल की जांच करने के निर्देश दिए । साथ ही जिले की 32 रेत खदानों में रेत की उपलब्धता के संबंध में सत्यापन शीघ्र कराने के निर्देश दिए । उन्होंने जिले में विभिन्न शालाओं के उन्नयन के प्रस्ताव विधायकों से प्राप्त कर शासन को

भेजने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए । साथ ही छात्रावास आश्रमों में पूर्व से कार्यरत वाटरमैन चौकीदार तथा रसोईयों के मानदेय कलेक्टर दर से कम प्राप्त हो रहा है जिसे बढ़ाने के लिए जिला योजना समिति के माध्यम से शासन को भेजने के निर्देश दिए । उन्होंने नमामि देवी नर्मदा नर्मदा सेवा यात्रा की तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और नर्मदा नदी के आस पास की पहाड़ियों पर विभिन्न संस्थाओं, एनजीओ, शासकीय विभागों को गोद देकर सघन वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए ।

इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनिता चौहान, विधायक अलीराजपुर श्री नागर सिंह चौहान, विधायक जोबट श्री माधौ सिंह डार, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राकेश अग्रवाल, कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री कार्तिकेयन के, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अनुग्रह पी, वनमण्डाधिकारी श्री अमित दुबे, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री काशीराम बडौले, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, जिला योजना अधिकारी श्री लोहारिया सहित समिति के सदस्य गण एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे ।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ में ध्वजारोहण



भोपाल । मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ में गणतंत्र दिवस पर प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने ध्वजारोहण किया । इस अवसर पर राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी श्री एस.के. जैन एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे । श्री रंजन ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ दीं ।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-

डी.सी.ए. मात्र 8100/-

**न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए.
स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)**

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित

सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध

प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल

(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)

ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039

फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160

Email: rajyasanghpl@yahoo.co.in, ccmtebpl@rediffmail.com

सुशासन की स्थापना के लिये जन-भागीदारी जरूरी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का मुम्बई में सुशासन में जन-भागीदारी विषय पर संबोधन



भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सुशासन की स्थापना जन-भागीदारी के बगैर सफल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाएँ और पंचायतें सुशासन की सर्वश्रेष्ठ इकाइयाँ बनें और अपनी सरकार का दर्जा व्यवहार में लागू हो। श्री चौहान मुम्बई में रामभाऊ म्हालगी प्रबोधनी कार्यक्रम में सुशासन में जन-भागीदारी राष्ट्रीय परिषद-2017 को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडनवीस भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सुशासन में जनता का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंचायत राज प्रणाली का संस्थागत और समग्र विकास किया जाना चाहिये। उन्हें

कानूनी और न्यायिक अधिकार मिलें, ताकि थानों और कचहरियों का बोझ घटे। उन्होंने कहा कि पंचायतों के सशक्त होने और संवैधानिक भूमिका निभाने से शासन और प्रशासन पर दबाव कम होगा और ग्रामीण क्षेत्र प्रशासनिक जटिलता की प्रक्रिया से मुक्त होंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्राम सभा विधायिका का दायित्व निभाने लगे, तो स्थानीय विविधता और अस्मिता की रक्षा होगी। गाँव स्वावलंबी बनेंगे। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में दायित्व का बोध होगा और उनके बीच व्याप्त उदासीनता समाप्त होगी। श्री चौहान ने कहा कि कृषि विकास की योजनाओं में भी किसानों की भागीदारी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो परम्पराएँ

चली आ रही हैं, उसमें योजनाएँ ऐसे लोग बनाते हैं, जो कभी न गाँव गये और न किसानों से मिले, उन्हें खेती-किसानी की भी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में इस परम्परा को समाप्त कर संबंधित वर्ग से संवाद कर योजनाएँ बनाने की शुरुआत की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को सफलता मिलने का राज ही यही है कि इसमें लोगों को भागीदार बनाया गया।

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बेटों के साथ भेदभाव से उन्हें काफी दुख होता था। हमने महिला पंचायत के जरिये महिलाओं से संवाद कर लाडली लक्ष्मी योजना बनायी है। गरीब बेटों के विवाह में

माता-पिता पर बोझ न आये, इसके लिये कन्या विवाह और निकाह योजना बनायी गयी। बुजुर्गों की इच्छा होती है कि वे तीर्थ-यात्रा करें। आर्थिक अभाव के कारण ऐसी यात्रा वे नहीं कर पाते थे। इसके लिये मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना की शुरुआत की गयी।

नमामि देवि नर्मदे-सेवा यात्रा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की जरूरत है कि हम नदियों को सुरक्षित और प्रदूषण से मुक्त करें। इसी उद्देश्य से मध्यप्रदेश में देश का सबसे बड़ा जल-संरक्षण और पर्यावरण अभियान चलाया जा रहा है। नर्मदा नदी की परिक्रमा कर लोगों को प्रदूषण न फैलाने और पौध-रोपण करने के लिये जागरूक बनाया जा रहा है। श्री चौहान ने

बताया कि लोगों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिये समाधान ऑनलाइन और सी.एम. हेल्पलाइन व्यवस्था शुरू की गयी है। वे स्वयं इसके जरिये लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं।

उन्होंने बताया कि आनंद मंत्रालय का गठन कर उन्होंने प्रदेश में लोगों को जीवन जीने का एक नया वातावरण उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडनवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में जन-भागीदारी की जो मिसाल कायम की है, वह पूरे देश में अनुकरणीय है।

कार्यक्रम के अंत में रामभाऊ म्हालगी प्रबोधनी के अध्यक्ष श्री विनय सहस्रबुद्धे ने आभार माना।

समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिये किसानों का पंजीयन शुरू

कुल 55 केन्द्रों पर होगी खरीदी

भोपाल। राज्य शासन के दिशा-निर्देशानुसार इस वर्ष भी समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिये व्यापक तैयारियाँ पूरी हो गयी हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिये इस वर्ष भी किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। पंजीयन का यह कार्य समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिये बनाये गये 55 केन्द्रों पर 14 जनवरी से एक साथ शुरू हो गया है जो कि आगामी 14 फरवरी तक जारी रहेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017-18 में गेहूँ खरीदी के लिए जो 15 नए केन्द्र बनाए गए हैं उनमें सेवा सहकारी केन्द्र रातीबढ़, धतूरीया,

भैंसाखेड़ी, तूमड़ा, भैंसाखेड़ी क्रमांक-2, किसान विपणन सहकारी समिति करोंद, बैरसिया क्रमांक एक व दो एवं भैंसाखेड़ी, वृहत्ताकार सहकारी समिति कजलास-फन्दा, मुगालिया छाप, कोडिया, टीलाखेड़ी, तरावली शामिल हैं।

जो किसान समर्थन मूल्य पर अपना गेहूँ बेचना चाहते हैं, उन्हें पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के लिये किसानों को अपना आधार नम्बर, समग्र आईडी, बैंक खाते का नम्बर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नम्बर आदि की जानकारी देना होगी। जिन किसानों का आधार

नम्बर नहीं आया है, उन्हें आधार का पंजीयन कराकर उसका पंजीयन नम्बर देना होगा। पंजीयन के समय निर्धारित फार्म के साथ ऋण पुस्तिका की छायाप्रति भी संलग्न करना है। यदि कृषक द्वारा किसी अन्य कृषक से भूमि सिकमी पर ली गयी है तो उसे अनुबंध-पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा। उपार्जन समितियों के पदाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे राज्य शासन के दिशा-निर्देशानुसार किसानों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उनका पंजीयन करें। पंजीयन संबंधित उपार्जन केन्द्र पर ही हो रहा है।

मुख्यमंत्री कृषक सहायता योजना राशि में वृद्धि

दुर्घटना में मृत होने पर मिलेगी 4 लाख रुपये की सहायता

भोपाल। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में सहायता राशि में वृद्धि की है। योजना में दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर 4 लाख की राशि दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 दिसम्बर 2016 को जम्बूरी मैदान में जन-कल्याण प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री कृषक सहायता योजना की राशि एक लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने की घोषणा की थी।

राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने घोषणा के पालन में सभी जिला कलेक्टर को दिये निर्देश में कहा है कि मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना-2008 में किये गये संशोधन के अनुसार अब किसानों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर बढ़ी हुई राशि 4 लाख रुपये आदेश दिनांक से दी जायें। योजना की शेष शर्तें पूर्व में जारी पात्रतानुसार होंगी। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री राकेश श्रीवास्तव ने योजना का जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा है।

राज्य कृषक आयोग की कार्य

अवधि में एक वर्ष की वृद्धि

श्री ईश्वरलाल पाटीदार अध्यक्ष नियुक्त

भोपाल। राज्य शासन ने राज्य कृषक आयोग की कार्य अवधि 25 जनवरी-2017 से 24 जनवरी-2018 तक एक वर्ष के लिये बढ़ाई है। साथ ही आयोग का अध्यक्ष रतलाम निवासी श्री ईश्वरलाल पाटीदार को नियुक्त किया गया है।

सहकारी बैंकिंग के विकास में वसूली की प्रक्रिया सहायक

समिति एवं बैंक कर्मियों के लिये वसूली प्रबंध पर प्रशिक्षण सम्पन्न

बालाघाट। सहकारी बैंकिंग के विकास में वसूली की प्रक्रिया की सक्रिय भूमिका है और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट में वसूली के जिले स्तर पर व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। वसूली के लिये प्रशिक्षण से समिति प्रबंधकों को ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी जो कि उनके कार्यक्षेत्र में सहायक सिद्ध होगी। ये विचार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट के अध्यक्ष श्री राजकुमार रायजादा ने बैंक के सभा भवन में वसूली प्रबंध पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये।

सहकारिता विभाग म.प्र. शासन एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के तत्वावधान में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में विशेष अतिथि के रूप में जिला



सहकारी केन्द्रीय बैंक के उपाध्यक्ष श्री महेन्द्र पटले ने कहा कि वसूली सहकारी साख का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर पैक्स प्रबंधकों को गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षण को एक सुअवसर निरूपित किया कि समिति प्रबंधकों को

विधिवत् व सार्थक जानकारी मिल सकेगी।

आयोजन की अध्यक्षता करते हुए श्री पी.एस. तिवारी, संयुक्त आयुक्त सहकारिता जबलपुर संभाग ने कहा कि माननीय आयुक्त सहकारिता म.प्र. शासन की परिकल्पना है कि वसूली प्रक्रिया को विकसित

करने हेतु राज्य स्तर पर विभागीय अधिकारियों व समिति प्रबंधकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जावें। कार्यक्रम की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जबकि पैक्स प्रबंधक निष्ठापूर्वक उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करें। कार्यक्रम में

प्र. सहायक आयुक्त श्री एस.एन. झारिया ने ऐसे प्रशिक्षण शिविरों को सार्थक और प्रभावी बताया।

स्वागत भाषण देते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री पी.एस. धनवाल ने कहा कि बैंक शासन की नीतियों के अनुरूप कार्य करने हेतु कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा जिले स्तर पर सदस्यता अभियान जारी है। जिसके सुपरिणाम से बैंक की सक्रियता प्रभावित होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करते हुए सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक व व्याख्याता श्री शशिकान्त चतुर्वेदी ने वसूली में वैधानिक प्रावधानों की चर्चा करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों एवं पैक्स प्रबंधकों की उपस्थिति उल्लेखनीय नहीं।

वसूली प्रबंधन एवं आडिट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न



शाजापुर। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं/सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा किये जा रहे वसूली प्रबंधन के प्रयासों के अंतर्गत संस्थाओं/बैंकों की वसूली में तेजी लाने के लिये सघन प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा वसूली एवं आडिट प्रशिक्षण के दो पाठ्यक्रम तैयार किये गये हैं। जिन पर पूरे प्रदेश में जिलेवार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक 16.01.2017 को शाजापुर/आगर

मालवा जिले के सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें म.प्र. राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षकों द्वारा वसूली कार्य से जुड़े कर्मचारियों को विधिवत् वसूली प्रक्रिया के सुचारु संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का मुख्य विषय "आडिट एवं वसूली प्रबंधन" रहा।

प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ श्रीमती सुनिता गोठवाल, उपायुक्त सहकारिता शाजापुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में श्री

के.एल. राठौर, प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर द्वारा प्रशिक्षण की उपयोगिता का महत्व बताते हुए विश्वास जताया कि ऐसे प्रशिक्षणों से कर्मचारियों का कौशल व व्यवहार दोनों ही अनुकूल होगा जिससे संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने में काफी मदद मिलेगी तथा श्री के. के. मालवी प्रशिक्षक द्वारा कार्यक्रम का संचालन करते हुवे वसूली एवं आडिट पर चर्चा की गई। अंत में सहकारिता विभाग जिला आगर/मालवा के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्री मुकेश भटनागर द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

प्रशिक्षण सम्पन्न

उज्जैन। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा सहकारी वसूली प्रबंध पर एक दिवसीय अल्पावधि प्रशिक्षण दिनांक 16.01.2017 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ श्री महेश कुमार माथुर, प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन द्वारा किया गया। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के प्राचार्य श्री पी.डी. गावशिन्डे एवं व्याख्याता श्री निरंजन कुमार कसारा द्वारा वसूली प्रबंध पर वसूली एवं बिक्री अधिकारियों को अधिनियम-नियम के अनुसार सम्पूर्ण जानकारी दी गई। उपायुक्त डॉ. मनोज जायसवाल एवं बैंक के महाप्रबंधक श्री डी.आर. सरोठिया ने भी सम्बोधित किया।

सत्र के द्वितीय चरण में सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आडिट विषय पर प्रशिक्षण डॉ. मनोज जायसवाल, उपायुक्त के शुभारंभ करने के साथ श्री पी.डी. गावशिन्डे, प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, आगर द्वारा आडिट विषय पर विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम में श्री निरंजन कसारा व्याख्याता द्वारा आभार प्रदर्शन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री जगदीश बैरागी भी उपस्थित रहे।

कैलेण्डर का विमोचन

जबलपुर। किसी भी सहकारी संस्था का वार्षिक कैलेण्डर समय प्रबंध के आधार पर क्रमबद्ध रूप से कार्यक्रम तैयार कर उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में सहायक होता है। इससे महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की जा सकती हैं। ये विचार प्रदेश के सामाजिक कल्याण एवं ग्रामीण पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने एम.पी. प्रिंटिंग प्रेस औद्योगिक सहकारी समिति के वार्षिक कैलेण्डर का विमोचन करते हुए स्टेडियम में व्यक्त किये। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री महेशचन्द्र चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक श्री एम.एस. सिकरवार ने भी वार्षिक कैलेण्डर को सहकारिता के विकास में सहायक बताया। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने सहकारिता की सार्थकता में सहकारी मुद्रणालयों की भूमिका पर प्रकाश डाला। एम.पी. प्रिंटिंग प्रेस औद्योगिक सहकारी समिति के प्रबंधक श्री के.के. तिवारी ने स्वागत भाषण देते हुए आभार व्यक्त किया।

(पृष्ठ 1 का शेष)

गण और तंत्र के रिश्तों को मजबूत बनाया सरकार ने

निर्धन व्यक्तियों को 5 रुपये प्रति थाली के मान से गुणवत्ता पूर्ण स्वादिष्ट भोपाल उपलब्ध होगा।

श्री चौहान ने कहा कि हर नागरिक को आवास देने के लिये एक नया कानून लाया जा रहा है जो आवासहीनों के लिए आवास या भूखंड उपलब्ध करवाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि आवासहीन नागरिकों को 2018 तक शहरी क्षेत्र में 5 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र में 8 लाख मकान उपलब्ध करवाए जायेंगे।

मिल-बाँचे मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षण स्तर को बेहतर बनाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिये 18 फरवरी को **मिल-बाँचे मध्य प्रदेश** कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़ें और इस दिन शाला में जाकर बच्चों के साथ किताब बाँचे, ज्ञान की बातें करें, आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का यदि राष्ट्रीय-स्तर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होता है तो उनकी पूरी फीस राज्य सरकार भरेगी। ऐसे विद्यार्थी जिनका 85 प्रतिशत से कम अंक होने पर भी राष्ट्रीय-स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में चयन होता है तो उन्हें भी शून्य ब्याज पर फीस की राशि दी जाएगी।

श्री चौहान ने कहा कि अभी तक एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन दिये गये हैं। बोर्ड की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को अब लेपटॉप की राशि के स्थान पर

(पृष्ठ 1 का शेष)

सहकारी बैंकों का सदस्य बनाने के लिए 'घर वापसी' अभियान

उन्होंने बताया कि मंथन की सिफारिशों के आधार पर की गयी कार्यवाही से कई सकारात्मक और बेहतर परिणाम सहकारी क्षेत्र को मिले हैं। उन्होंने बताया कि सितम्बर से दिसम्बर, 2016 तक सहकारी बैंकों के डिपाजिट में वृद्धि हुई है। धान और मक्का उपार्जन के बाद 400 करोड़ रुपये की वसूली हुई है, जो पूर्व में मात्र 100 करोड़ होती थी। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने भी इस वर्ष पुनर्वित्त योजना में अपेक्स बैंक को

लेपटॉप दिए जाएंगे। सभी विश्वविद्यालयों में बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन शुरू किया जायेगा। गरीबों को दो लाख तक फ्री उपचार स्वास्थ्य सुविधाएँ सुलभ करवाने के प्रयासों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवार के मरीजों को दो लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जायेगी। सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय **मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर** अलग-अलग तिथियों में लगाए जाएंगे। इन शिविरों में जाँच कर आगे इलाज की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया वे ऐसे मरीजों की जानकारी मिलने पर उन्हें शिविर में लेकर आएँ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद और होम्योपैथी डॉक्टरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थ किया जाएगा, जहाँ डॉक्टर का पद रिक्त है। उन्होंने कुपोषण दूर करने के प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं में खून की कमी को रोकने और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिये लालिमा योजना लागू की गई। अटल बाल मिशन के जरिये समुदाय को पोषण सुधार की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। स्नेह सरोकार कार्यक्रम के जरिये जन-भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन प्रयासों से पिछले 10 साल में गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 12.06 से घटकर 9.2 प्रतिशत हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल-प्रदाय

व्यवस्था सुदृढ़ होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल-प्रदाय व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए एक वर्ष में नल-जल योजनाओं के माध्यम से 5,000

बसाहटों में तथा नए हैण्डपंप लगाकर 10,000 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर राज्य सरकार किसानों की आय पाँच वर्षों में दोगुनी करने के रोडमैप पर तेजी से काम कर रही है। इस वर्ष 14 अप्रैल से ग्रामोदय अभियान के साथ कृषि महोत्सव भी मनाया जायेगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में खरीफ 2015 के लिये प्रदेश के 20 लाख 47 हजार किसानों को 4 हजार 416 करोड़ की फसल बीमा दावा राशि वितरित की गई। देश में इतनी बड़ी बीमा राशि भुगतान का यह अनूठा मामला है। इसके अतिरिक्त आपदा राहत के रूप में 4 हजार 835 करोड़ की राहत राशि बाँटी गई है। एक वर्ष में विभिन्न मदों में 18 हजार 444 करोड़ की सहायता किसानों को उपलब्ध करवाई है।

श्री चौहान ने कहा कि 20 कृषि मण्डी समितियों को राष्ट्रीय कृषि मण्डी से जोड़ा जा चुका है तथा 30 और मंडियों को इस वर्ष जोड़ने की योजना है। दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में अब 2 गावों के स्थान पर न्यूनतम 5 गाएँ देने की व्यवस्था की गई है।

सरकारी स्रोतों से लगभग 40 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है जिसे वर्ष 2025 तक 60 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। अब नहरों से पानी ले जाने की बजाय पाईप से दबावयुक्त पानी ले जाकर ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। इससे उतने ही पानी से दो से चार गुना क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। अनेक राज्य मध्यप्रदेश की इस पहल का अध्ययन कर रहे हैं।

ऊर्जा में आत्म-निर्भरता की

हो जायेगा।

सहकारिता रा%य मंत्री ने बताया कि सहकारिता क्षेत्र का विस्तार किया गया है। बहु-उद्देश्यीय दुकानों में 250 वस्तुएँ विक्री के लिये रखी जायेंगी। बिल्डिंग मटेरियल बैंक बनाये जायेंगे और उचित मूल्य दुकानों से निर्माण सामग्री का विक्रय किया जायेगा। सहकारिता के क्षेत्र में ई-रिक्शा के 11 रूट का आवंटन हुआ है। इसका और विस्तार किया जायेगा।

चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि घरों में 24 घंटे और कृषि पम्पों के लिये 10 घंटे प्रतिदिन बिजली मिल रही है। इस वर्ष से **मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन योजना** में जून 2019 तक 5 लाख अस्थाई कनेक्शन को स्थाई में बदला जायेगा। इस वर्ष नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 24 प्रतिशत की वृद्धि से प्रदेश देश में प्रथम है। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ बल्बों का इस्तेमाल कर बिजली बचाएँ।

सड़कों के विकास में हुई प्रगति को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 5500 किलोमीटर नये राष्ट्रीय राजमार्ग और 3778 किलोमीटर नये राज्य राजमार्ग घोषित किये गये हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक लगभग 6 हजार गाँवों को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है।

युवा सशक्तिकरण मिशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को कौशल सम्पन्न बनाने के लिए युवा सशक्तिकरण मिशन चलाया जाएगा जिसमें मिशन के तहत हर वर्ष साढ़े सात लाख युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जाएगा। भोपाल में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य को प्राथमिकता से किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ 24 लाख बालिकाओं को मिल चुका है। इस शिक्षा सत्र में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाली लाडलियों को 2000 रूपये की छात्रवृत्ति ई-पेमेंट से दी जा रही है। संविदा शिक्षक में 50 प्रतिशत और वन विभाग को छोड़कर अन्य नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। पुलिस भर्ती में भी यह आरक्षण किया गया है। लाडो अभियान से अभी तक 82 हजार से ज्यादा बाल विवाह समझाइश से रोके गये हैं। अभियान को प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार और कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है।

स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य है। नगरों के सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा

कि स्मार्ट सिटी योजना में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन शामिल हुए हैं।

नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए चल रहे नगर उदय अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने नागरिकों से अभियान में सक्रियता के साथ भाग लेने का आग्रह किया। औद्योगिक विकास के लिए उठाये गए कदमों की चर्चा कार्य करते हुए उन्होंने कहा कि 2400 करोड़ की लागत से 15 नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति 2016 की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं का अगले साल साढ़े सात लाख युवाओं को लाभ दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास का संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वर्गों के विकास के लिए 5 वर्षीय सर्वांगीण विकास योजना का कम्पोजिट पैकेज तैयार किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सभी जिलों में छात्रावास शुरू किए गए हैं और लगभग सवा चार लाख विद्यार्थियों को छात्रावास का लाभ मिल रहा है। संत रविदास और कबीर जैसे सर्वधर्म समभाव की प्रेरणा देने वाले संतों के जन्म-दिवस पर सामाजिक समरसता लाने के लिये जन-जागरण कार्यक्रम किये जायेंगे। सुदूर वनांचलों में **दीनदयाल वनांचल सेवा** से वनवासियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की पहल की गयी है।

प्रदेश पर्यटकों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। जल-पर्यटन के क्षेत्र में हनुवतिया का विशिष्ट स्थान है, जहाँ दूसरे जल-महोत्सव में 5 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ। गाँधीसागर, बाणसागर सहित अन्य जल-पर्यटन केन्द्र विकसित किये जा रहे हैं। पर्यटन केबिनेट का गठन किया गया है। राष्ट्र की सुरक्षा में जीवन बलिदान करने वाले वीर सैनिकों की स्मृति को यादगार बनाने के लिये अनूठी पहल करते हुए भोपाल में शौर्य स्मारक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना का लाभ पिछले साल एक लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को मिला है। इस वर्ष से पटना साहिब, गंगासागर और प्रदेश के तीर्थ-स्थानों को भी शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना

भोपाल। मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में फरवरी से अप्रैल के मध्य 16 जिलों के लगभग 6, 806 तीर्थ यात्री पुरी, द्वारका, शिडी, वैष्णोदेवी तथा रामेश्वरम तीर्थ-स्थल की यात्रा करेंगे।

बुरहानपुर से 14 फरवरी को 973 यात्री पुरी के लिए रवाना होंगे। बुरहानपुर से 97 यात्री, खण्डवा-171, खरगोन-245, बड़वानी-181, हरदा-74 तथा बैतूल से 205 यात्री जायेंगे।

दिनांक-15 मार्च को भी शिवपुरी, दतिया, शहडोल तथा अनूपपुर से 973 यात्री पुरी जायेंगे। इसमें शिवपुरी से 333, श्योपुर-134, दतिया-152, शहडोल-207 तथा अनूपपुर से 147 यात्री शामिल हैं। द्वारकाधाम के लिए बुरहानपुर से 1 मार्च को 83 यात्री, खण्डवा-123, खरगोन-166, बड़वानी-127, भोपाल-225, रायसेन-125 तथा सीहोर से 123 यात्री रवाना होंगे। इसी तरह द्वारका के लिए 30 मार्च को भी अनूपपुर-231, शहडोल-337 तथा कटनी से 406 यात्री रवाना होंगे। शिडी के लिए 8 मार्च को कुल 972 यात्री जायेंगे। जिसमें शिवपुरी से 135, श्योपुर-49, ग्वालियर-155, भोपाल-182, रायसेन-101, खण्डवा-100, खरगोन-144 तथा बड़वानी से 105 यात्री जायेंगे। वैष्णोदेवी तीर्थ-दर्शन के लिए 26 मार्च को बुरहानपुर से 72, खण्डवा-115, खरगोन-147, बड़वानी-116, भोपाल-202, रायसेन-113, शिवपुरी-155 तथा श्योपुर से 49 यात्री जायेंगे। दिनांक 31 मार्च को रामेश्वरम के लिए कटनी से 401 यात्री, शहडोल से 337 तथा अनूपपुर से 236 यात्री रवाना होंगे।

गेहूँ उपार्जन में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें**मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा**

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गेहूँ उपार्जन में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। इसके लिये कड़ा कानून बनाने का प्रस्ताव लायें। उन्होंने कहा कि गेहूँ उपार्जन के केन्द्र किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाये जायें। मुख्यमंत्री मंत्रालय में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा कर रहे थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि

गेहूँ उपार्जन के केन्द्र दूरी को ध्यान में रखकर व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त स्थानों पर ही नियत किये जायें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गेहूँ उपार्जन में अनियमितताएँ बरती हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये। इसके लिये शीघ्र कड़ा कानून प्रस्तावित किया जाये। खरीदी पारदर्शी व्यवस्था से की जाये तथा बारदाना आदि की पर्याप्त व्यवस्था हों। श्री चौहान ने कहा कि समर्थन मूल्य पर उपार्जन किये गये मक्का को केन्द्रीय पूल में लेने के लिये

प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे।

श्री चौहान ने कहा कि सस्ते राशन वितरण से कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं। पात्रता परीक्षण का राज्यव्यापी अभियान चलाया जाये। जिला-स्तर, विकासखण्ड-स्तर और उचित मूल्य की दुकान स्तर पर निगरानी समितियों के गठन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाये। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के

निराकरण में शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये।

बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री के.सी. गुप्ता, आयुक्त खाद्य श्री फैज अहमद किदवई तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को मिलाने से बढ़ेगी पौष्टिकता

भोपाल। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाकर फोर्टिफाइड करने से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाली एनीमिया, रेकेट्स आदि बीमारियों से लोगों को बचाया जा सकता है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह ने यह बात भोपाल में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानकीकरण प्राधिकरण द्वारा की गई **फूड-फोर्टिफिकेशन** क्षेत्रीय संगोष्ठी में कही। अध्यक्षता भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आशीष बहुगुणा ने की। संगोष्ठी में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

श्री आशीष बहुगुणा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन करने के पहले उपभोक्ताओं व्यापारियों एवं क्रियान्वयन तंत्र के पक्षों की राय जानने के बाद निष्कर्षों पर कार्य किया जाये। प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया ने कहा कि प्रदेश में कुपोषण मिटाने के विरुद्ध किये जा रहे हर सार्थक पहल का स्वागत है। स्कूल शिक्षा सचिव श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने कहा कि कुपोषण मुक्त बच्चे शिक्षा, खेल और भविष्य निर्माण की गतिविधियों में बेहतर कर सकते हैं। स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने कहा कि देश में अनाज, तेल एवं दूध में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाने का कार्य किया जा रहा है। इसे प्रदेश में लागू करने के लिये भी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

विषय-विशेषज्ञों ने कार्यक्रम में फूड-फोर्टिफिकेशन के क्षेत्र हो रहे प्रयोगों, अनुभवों और तकनीकी पक्षों पर प्रस्तुतिकरण दिया। ग्लोबल एलाउंस ऑन इम्पुल्स न्यूट्रिशन (गेन), माइक्रो न्यूट्रियंट इनिशियटिव, सीएचआई आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ भी आयोजन में सहभागी थीं।

स्थानीय अवकाश घोषित

भोपाल। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2017 के लिए भोपाल स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं। इनमें रंगपंचमी शुक्रवार 17 मार्च, गणेश चतुर्थी शुक्रवार 25 अगस्त और दीपावली का दूसरा दिन शुक्रवार 20 अक्टूबर है। भोपाल गैस त्रासदी दिवस 3 दिसम्बर रविवार को होने के कारण अलग से स्थानीय अवकाश घोषित नहीं किया गया है।

अंकेक्षण और वसूली की प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण

बालाघाट। सहकारी बैंकिंग के सफल संचालन हेतु अंकेक्षण और वसूली की प्रक्रिया का निर्वाह सफलता पूर्वक होना जरूरी है और इसका दायित्व सहकारिता विभाग के अधिकारियों के उपर निर्भर है। ये अधिकारी कुशलता पूर्वक इस महत्वपूर्ण कार्य को कर सके इसके लिये उन्हें दक्ष होना जरूरी है और दक्षता वृद्धि हेतु प्रभावी प्रशिक्षण का होना

आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. के निर्देशानुसार राज्य स्तर पर सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश शासन एवं म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के तत्वाधान में विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। ये विचार सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने

बालाघाट में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर में व्यक्त किये।

बालाघाट में उप आयुक्त सहकारिता विभाग के कार्यालय में जिले के विभिन्न अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के व्याख्याता श्री शशिकान्त चतुर्वेदी ने व्यापक रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया। श्री चतुर्वेदी ने म.प्र. सहकारी अधिनियम के संवैधानिक प्रावधान धारा 56, धारा 58, धारा 58 बी, धारा 84 धारा 85 के अनुसार अंकेक्षण व वसूली की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के अन्त में आभार प्रदर्शन प्रभारी सहायक आयुक्त श्री एस.एन. झारिया द्वारा किया गया। आयोजन में जिला सहकारी संघ के प्रभारी अधिकारी श्री एस.एल. पन्डे, प्रबंधक श्री आर.के. राय एवं प्रचार अधिकारी श्री मुकेश दुबे का सहयोग सराहनीय रहा।



68वां गणतंत्र दिवस

भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान
लोकतंत्र के जग में इसकी सबसे ऊँची शान

गणतंत्र दिवस की
हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश



“त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवि नर्मदे”

नर्मदा सेवा यात्रा

प्रारम्भ - 11 दिसम्बर, 2016 | समापन - 11 मई, 2017
अमरकंटक में नर्मदा के दक्षिण तट से... | अमरकंटक में नर्मदा के उत्तर तट पर।

समाज और सरकार का सामूहिक संकल्प

- 16 जिलों के 1100 गाँवों में 3350 किलोमीटर की यात्रा।
- नर्मदा तटों पर एक किलोमीटर के दायरे में व्यापक वृक्षारोपण।
- अपने खेतों पर वृक्ष लगाने वाले किसानों को दी जायेगी 3 वर्ष तक 20 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से सहायता।
- नर्मदा के दोनों तटों पर पांच किलोमीटर की सीमा तक नहीं होंगी शराब की दुकानें।
- नर्मदा तटों पर स्थित समस्त नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 1500 करोड़ की राशि स्वीकृत।
- नर्मदा तटों के दोनों तरफ 1 किलोमीटर की सीमा में स्थित सभी ग्राम होंगे ओडीएफ।
- नर्मदा सेवा कार्यों को स्थायित्व देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में नर्मदा सेवा समिति का गठन।

विश्व का सबसे बड़ा नदी संरक्षण अभियान



मध्यप्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा की सेवा को उमड़ा जनसैलाब

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : 0755-4911102, 4911103, वेबसाइट : namamidevinarmade.mp.gov.in

Follow Chief Minister Madhya Pradesh /CMMadhyaPradesh /CMMadhyPradesh /ChouhanShivrajSingh

आवृत्त : म.प्र. माघ/2017

D-80304/17